



हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर



वर्ष:4 अंक:270 पृष्ठ:08 मूल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, शनिवार, 04 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में जनहानि होने पर पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मां दुर्गा का वाहन शेर, गणेश का वाहन मूषक, मां सरस्वती का हंस, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी का उल्लू और महादेव के गले में नागराज व उनके साथ नंदी - यह सब हमारे सनातन जीवन दर्शन में मानव और जीव-जगत के सहअस्तित्व के प्रतीक हैं। यही कारण है कि आदिकाल से भारत की जीवन पद्धति में वन्यजीव संरक्षण स्वाभाविक रूप से शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की लगभग 14.77 प्रतिशत भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है। यह अनुपात देश की तुलना में कहीं अधिक है, जो राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की हरियाली और यहां



विचरण करने वाले वन्य जीव देश-विदेश से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सरकार पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ-साथ वनों और वन्य जीवों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि हर जिले में कम से कम एक

नए पर्यटन स्थल की पहचान कर उसे विकसित किया जाए, लेकिन उसका प्राकृतिक स्वरूप नष्ट न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हुई है, हालांकि मानव-वन्य जीव संघर्ष की चुनौती भी बढ़ी है। इसे कम करने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रही है। वन विभाग को ड्रोन और जीपीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि निगरानी और सुरक्षा प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से



जोड़ने के लिए 'सीएम यंग ईको-प्रिन्योर' योजना को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और ईकोटूरिज्म आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के माध्यम से शैक्षिक यात्राओं का आयोजन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पर्यटकों से अपील की कि वे जंगल सफारी या धार्मिक स्थलों पर जाते समय गंदगी न फैलाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 'लाइफ

स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' अभियान धरती मां को बचाने का मंत्र है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के संतुलन से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, राज्य सभा सांसद नरेश बसंत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) रंजन कुमार मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मोदी आज करेंगे 62,000 करोड़ रुपये की युवा-केंद्रित पहलों का लोकार्पण

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजधानी दिल्ली में शनिवार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की युवा विकास पहलों का लोकार्पण करेंगे, जिससे देश भर में युवाओं को शिक्षा, कौशल और उद्यमिता की दिशा में बढ़ावा मिल सकेगा।

इन युवा विकास पहलों के केंद्र में बिहार में युवा कौशल और शिक्षा को रखा गया है, जिसके अंतर्गत बिहार के पांच लाख स्नातकों को दो साल तक मासिक भत्ता, बिहार के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नयी शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखने के साथ ही बिहटा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना के नये परिसर के साथ ही कई अन्य योजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में चौथा राष्ट्रीय कौशल दीक्षा समारोह के साथ विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने



वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 46 अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ युवा को सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर श्री मोदी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र की पीएम-सेतु (अपग्रेडेड आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन) योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई का हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नयन करने की परिकल्पना की गयी है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई

शामिल हैं। प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेडिंग, डिजिटल शिक्षण प्रणाली और इनक्यूबेशन सुविधाओं से युक्त समूह तैयार किये जायेंगे। परियोजना कार्यान्वयन के प्रथम चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

इस अवसर पर श्री मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। इन प्रयोगशालाओं में दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों सहित, सूचना-प्रौद्योगिकी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसद और पर्यटन जैसे 12 उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप उद्योग-प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने और रोजगार के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करने के लिए 1,200 व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी शामिल है।

समाज के भीतर सेवा, दान की परंपरा उसकी सबसे बड़ी शक्ति : बिरला

जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समाज के भीतर सेवा और दान की परंपरा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही भविष्य को नई दिशा देती है।

श्री बिरला ने यहां शुक्रवार को राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा आयोजित प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह में कहा कि सेन समाज ने हमेशा सेवा, श्रम और समर्पण को सर्वोच्च धर्म मानते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। यह समाज शिक्षा, कौशल और संस्कारों के माध्यम से आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति और सामूहिक मूल्यों का सम्मान है। समाज के भीतर सेवा और दान की परंपरा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही भविष्य को नई दिशा देती है।

उन्होंने कहा कि सेनजी महाराज ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि श्रम ही सर्वोच्च पूजा है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। वहीं, नारायणी माता आस्था और विश्वास की आधारशिला हैं, जिनके आशीर्वाद से समाज ने अपनी परंपराओं और संस्कारों को सदियों से जीवित रखा है। यही कारण है कि यह समाज हर दौर में चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र



की सेवा में आगे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय नाई महासभा की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि संगठन पूरे देश में रक्तदान शिविर, चिकित्सा सेवाएँ, नशा मुक्ति अभियान और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। छात्रवृत्ति, कोचिंग और करियर मार्गदर्शन जैसी योजनाएँ युवाओं को नई राह दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रतिभाएं मंच पर सम्मानित होती हैं तो उनमें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागता है, जो समाज को नई ऊँचाइयों तक ले जाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सेनजी महाराज के आदर्शों और नारायणी माता की शिक्षाओं को जीवन का हिस्सा बनाएं। शिक्षा, कौशल और तकनीक को अपनाकर आत्मनिर्भर बनें और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाएं।

राहुल विदेश में देश की छवि खराब करने का कर रहे हैं काम : भाजपा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यह आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि श्री गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लिए शूल है।

श्री त्रिवेदी ने कहा कि देश में पिछले 36 घंटे में दो प्रकार के दृश्य देखने को मिले हैं, पहला 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर



समर्पित विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक

संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का देशभर में समारोह होना। इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मां भारती के अंकित चित्रों वाला 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। दूसरी तरफ देश की 140 साल पुरानी पार्टी के नेता ने विदेश की धरती से एक और देश विरोधी बयान दिया है, जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स ने जनवरी 2023 में कहा कि भारत ने कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था में जिस तेजी से

संस्थानिक सुधार (स्ट्रक्चर रिफॉर्म) किया है उससे वह बहुत शक्तिशाली बना है। उन्होंने कहा कि सवाल यह उठता है कि कांग्रेस नेता श्री गांधी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें कैब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हुई केस स्टडी और स्टेनफोर्ड द्वारा तैयार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इंडेक्स, जिसके अनुसार भारत एआई कौशल निवेश में पहले स्थान पर और एआई जीवंतता में शीर्ष चार देशों में शामिल है क्यों नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी इसी स्टेनफोर्ड

यूनिवर्सिटी में जाकर भारत के बारे में अपशब्द, अपमानजनक और निरर्थक बातें करते हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसके लिए उन्हें विदेश के विश्वविद्यालय बुलाते हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें नहीं बुलाया जाता। श्री त्रिवेदी ने कहा कि जब श्री गांधी को भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें भारत के बाहर ही क्यों बुलाया जाता है।



पार्षद अहसान अंसारी ने पर्यावरण मित्रों को किया सम्मानित

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। वार्ड 44 त्रिमूर्ति नगर के पार्षद अहसान अंसारी ने शुक्रवार को पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पार्षद अहसान अंसारी ने कहा कि वार्ड में साफ सफाई बनाए रखने में पर्यावरण मित्र अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वार्ड 44 को नगर निगम का सबसे आदर्श वार्ड बनाना उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरण मित्र अहम सहयोग दे रहे हैं। साफ सफाई बेहतर होगी तो वातावरण स्वच्छ बनेगा। जिससे संक्रामक रोगों पर अंकुश लगेगा। अहसान अंसारी ने वार्ड वासियों ने सहयोग की अपील करते हुए कहा कि डेंगू व मच्छर जनित कई प्रकार के रोग फैल रहे हैं। ऐसे में अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता बनाए रखने में मदद कर रहे पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन



करें। उन्होंने कहा कि वार्ड में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का भी इसमें सहयोग लगातार मिल रहा है। इस दौरान सेनेटरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक कुसुम पाल

ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। घरों का कूड़ा इधर-उधर ना फेंकें, नियत स्थान पर कूड़ा डालें और पर्यावरण मित्रों का सहयोग करें।

नौकरी का झाँसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को यूपी से पकड़ा

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। नौकरी का झाँसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को चकमा दे रहा था।

पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को पीड़िता द्वारा थाना भगवानपुर पर तहरीर दी गई थी कि लोकेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी जगेता गुज्जर, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर द्वारा नौकरी का झाँसा देकर तथा अपने ऊँची पहुँच का भय दिखाकर उसे बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता की



शिकायत के आधार पर थाना भगवानपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला शोषण से संबंधित गंभीर अपराध होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। भगवानपुर पुलिस द्वारा गठित टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं मुखबिर तंत्र के सक्रिय होने पर आरोपित लोकेश कुमार को शुक्रवार को स्टेट बैंक कॉलोनी तिराहा, दिल्ली रोड, सहारनपुर से हिरासत में लिया गया। आरोपी लंबे समय से युवतियों को नौकरी का लालच देकर तथा राजनीतिक प्रभाव दिखाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

हरकी पैड़ी जलविहीन, वार्षिक रखरखाव के लिए 15 दिनों तक गंगनहर बंद

पथ प्रवाह संवाददाता, हरिद्वार।

हरिद्वार की पहचान और आस्था का केंद्र हरकी पैड़ी शुक्रवार को जलविहीन हो गई। कारण था गंगनहर की वार्षिक बंदी। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगनहर को हर साल दशहरे की रात से छोटी दिवाली तक मेंटेनेंस और साफ-सफाई के लिए बंद किया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी भीमगोड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहर का प्रवाह रोक दिया।

सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर असर

नहर बंदी के चलते इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्य प्रभावित होंगे और दिल्ली-एनसीआर में पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ ने बताया कि गंगनहर साल भर निरंतर संचालित होती है, इसलिए इसके मरम्मत और रखरखाव कार्य बेहद जरूरी हैं। हर वर्ष इसी अवधि में नहर को बंद कर कार्य पूरे किए जाते हैं। विभाग के अनुसार छोटी दिवाली की रात को गंगाजल पुनः छोड़ा जाएगा।

सिक्कों की खोज में जुटे लोग

हरकी पैड़ी और आसपास के घाट



जलविहीन होने के बाद सुबह से ही स्थानीय लोग गंगा की तलहटी में सिक्के और आभूषण ढूँढने में जुट गए।

मालवीय द्वीप घाट और हरकी पैड़ी पर कई लोग सुबह तड़के से ही रेती में कुछ पाने की उम्मीद से उतर आए। दिनभर घाट पर सिक्के ढूँढने का सिलसिला चलता रहा। जिनके हाथ कुछ लग गया, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी।

श्रद्धालुओं और व्यापारियों में निराशा

गंगाजल न मिलने से श्रद्धालु निराश हुए। बाहर से आए यात्री आस्था की डुबकी नहीं

लगा सके और मायूस लौट गए। वहीं, स्थानीय व्यापारियों ने भी चिंता जताई। उनका कहना था कि भले ही गंगनहर का रखरखाव जरूरी है, लेकिन हरकी पैड़ी पर आस्था को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना जल जरूर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालु स्नान कर सकें।

दिवाली की रात लौटंगा गंगाजल

सिंचाई विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बंदी केवल वार्षिक रखरखाव के लिए है। छोटी दिवाली की रात को गंगाजल छोड़े जाने के बाद हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर फिर से गंगा प्रवाहित होगी।

युद्ध शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को ताम्र कलश में संग्रहित कर लैंसडौन भेजा

पथ प्रवाह संवाददाता।

पिथौरागढ़। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीडीहाट द्वारा तीन युद्ध शहीदों के घर- आंगन की पवित्र मिट्टी को ताम्र कलश में संग्रहित कर डीडीहाट से लैंसडौन (पौड़ी गढ़वाल) भेजा गया।

यात्रा का शुभारंभ कर्नल करम सिंह बिष्ट (सेवानिवृत्त), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ और पिंकी आर्या, तहसीलदार डीडीहाट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रामलीला मैदान डीडीहाट से किया गया। इस यात्रा में शहीदों के परिजन और आश्रित भी शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। यह शहीद सम्मान समारोह 5 अक्टूबर को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेन्टर



लैंसडौन में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें ताम्र पत्र भेंट

किए जाएंगे। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में 35 पूर्व सैनिक शामिल रहे।

एक नजर

एसपी क्राइम व ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने एम्स में लगायी साइबर अवेयरनेस पाठशाला



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात जितेंद्र मेहरा (ट्रैफ़्क) द्वारा एम्स ऋषिकेश में एक विशेष साइबर अवेयरनेस पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति युवाओं, विशेषकर चिकित्सकीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेनी डॉक्टरों/ कार्यरत स्टाफ को सजग और सतर्क बनाना है। पाठशाला में एम्स ऋषिकेश के कार्यरत लगभग 150 स्टाफ ने भाग लिया। साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार जैसे डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी अपडेट फ्रॉड, ओटीपी शेयरिंग धोखाधड़ी, आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार छोटी-सी लापरवाही व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्षति पहुँचा सकती है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, एम्स प्रशासन द्वारा पुलिस के इस आयोजित प्रोग्राम की काफी सराहना की गई।

कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत की शिकायत पर ऑडियो विलप की जांच शुरू

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र और हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने आरोप लगाया है कि एक महिला और पुरुष के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज होने का दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र रावत का कहना है कि झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनैतिक षड़यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि पुलिस को पूरे मामले की जांच कर षड़यंत्र करने वालों को बेनकाब करना चाहिए और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि ऑडियो क्लिप को कई सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो स्टोन क्रेशर किये सीज



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम नेहन्दपुर में अवैध खनन की शिकायत पर की गई कार्रवाई में दो स्टोन क्रेशर सीज कर दिये गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को शिकायत मिल रही थी कि कुछ स्टोन क्रेशरों द्वारा अभी भी अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा दिए निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी लक्सर और जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में खनन तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स लिमरा स्टोन क्रेशर को सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर उर्फ बुधवा शहीद में स्थित मैसर्स राज स्टोन क्रेशर जो बिना नवीनीकरण के संचालित किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर तहसीलदार भगवानपुर व जिला खान अधिकारी के द्वारा मौके पर पहुँचकर क्रेशन को सीज करते हुए उसका मेन गेट भी सील कर दिया गया।



एक नजर

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दबोचा



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने थाना सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2025 को वादी की नाबालिक पुत्री के साथ आरोपी प्रकाश केशव पुत्र केशव निवासी जुर्स कन्ट्री कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार द्वारा अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोतवाली ज्वालापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। टीमों द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपना जाल बिछाया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसने घटना के दिन से ही अपना मोबाइल नंबर बन्द कर लिया था। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल के रह रहा था। पुलिस आरोपी के मकान और रिश्तेदारों के अलावा अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब बीती 2 अक्टूबर को आरोपी प्रकाश केशव थाना सिडकुल क्षेत्र से पकड़ लिया गया।

शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में तीन पर कार्रवाई



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार/लक्सर। शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में लक्सर कोतवाली पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। कोतवाली लक्सर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर तीनों आरोपी आपस में झगड़ा कर रहे थे। इनके द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित होने पर तीनों को भिक्कमपुर क्षेत्र से हिरासत में लेकर धारा 170 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई। आरोपियों के नाम सूर्यप्रताप पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मजलिसपुर तौफिर, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर (30प्र0), पारस पुत्र रामकुमार निवासी समाना उर्फ रामराज, थाना रामराज, जिला मुजफ्फरनगर (30प्र0), अनिल पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम रामपुर रायघटी, थाना कोतवाली लक्सर, जनपद हरिद्वार है।

शांति चोरों को चोरी के माल के साथ किया गिरफ्तार



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। थाना बहादुराबाद पुलिस ने दो शांति चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के पास से निर्माणाधीन पुल से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। थाना बहादुराबाद के मुताबिक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से सामान चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जहां पर शैलेन्द्र कुमार (इंजीनियर) द्वारा पुलिस टीम के साथ मिलकर निर्माणाधीन पुल में प्रयोग होने वाले स्टीव, शोकर (लगभग 20 पीस) चोरी करने वाले आरोपी अजीम पुत्र नसीम व इमरान पुत्र इकबाल निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी रूडकी कोतवाली, सिविल लाईन रूडकी को चोरी किये गये शत प्रतिशत माल के साथ पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना बहादुराबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

ग्रामोत्थान रीप परियोजना के अभिनव उद्यमों की सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने की समीक्षा

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के अंतर्गत संचालित इनोवेटिव सीडीओ (सामुदायिक आधारित संगठन) स्तरीय उद्यमों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य परियोजना की अभिनव गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करना तथा लाभार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर समाधान हेतु विस्तृत चर्चा करना था।

समीक्षा बैठक में नारसन विकासखंड से तीन इनोवेटिव गतिविधियों के लाभार्थी और उनके संबंधित सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। लाभार्थियों ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने में आने वाली समस्याओं, उनके निवारण के लिए सुझावों और भविष्य की वे-फॉरवर्ड रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। सीडीओ के साथ, मुख्य उद्यान अधिकारी, डेयरी विभाग और डेयूटी सीडीओ ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना, समस्त



सहायक प्रबंधक, खंड विकास अधिकारी नारसन सुभाष सैनी तथा नारसन विकासखंड स्तरीय रीप और एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की पूरी टीम ने भी प्रतिभाग किया। चर्चा के उपरांत, सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने परियोजना की प्रगति को देखते हुए रेखीय विभाग के अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी नारसन विकासखंड के इन इनोवेटिव उद्यमों का भौतिक भ्रमण करेंगे। इस भ्रमण के दौरान वे गतिविधियों के संचालन में आ रही समस्याओं और सुझावों

को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

सीडीओ ने निर्देशित किया कि यह विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही उनके (सीडीओ) समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि प्राप्त तथ्यों के आधार पर इन उद्यमों को मजबूती प्रदान करने और गति देने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाई जा सके। यह पहल लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और परियोजना के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

हरिद्वार में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत एकत्रित की गई शहीद के आंगन की मिट्टी

पथ प्रवाह संवाददाता।

उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारम्भ 25 सितम्बर से किया जा रहा है जिसे 4 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। जनपद हरिद्वार के 2 शहीदों के घर-आंगन की मिट्टी संग्रह का कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण एव पुनर्वास कार्यालय, ज्वालापुर तहसील, हरिद्वार से प्रारम्भ किया गया। यात्रा शहीद हवलदार सोनित कुमार सैनी, जो दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को अरुणांचल प्रदेश के ढुकुमपानी क्षेत्र में शहीद हुए थे, के ग्राम धनौरा, ब्लाक-रूडकी में पहुंची। समस्त ग्रामवासियों द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि के पश्चात शहीद सैनिक की पत्नी गीता सैनी द्वारा घर-आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को हस्तगत किया गया।

तत्पश्चात् शहीद सम्मान यात्रा जनपद के द्वितीय शहीद नायक प्रदीप कुमार, जो कि दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को सिक्किम क्षेत्र में शहीद हुए थे, के ग्राम गदरजुड़ा के लिये प्रस्थान किया, जहां पर नारसन ब्लाक प्रमुख कविन्द्र चौधरी, ग्राम प्रधान गदरजुड़ा भूपेन्द्र सिंह व समस्त ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया। शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि के पश्चात शहीद सैनिक की पत्नी कविता चौधरी एवं



परिवार के सदस्यों द्वारा घर-आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को हस्तगत किया गया।

इस दौरान जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर डॉ सरिता पवार ने बताया कि प्रदेश सरकार शहीदों के आंगन की मिट्टी से देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कर रही है ताकि उनकी वीरगाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को गढ़वाल राईफल रेजीमेंट सेन्टर लैसडौन में 'शहीद सम्मान समारोह' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद वीरनारियों सहित प्रदेश की समस्त वीरनारियों को मुख्यमंत्री द्वारा ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित

किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम में जनपद हरिद्वार के वीर नारियों व उनके आश्रितों के प्रतिभाग करने हेतु फ्लैग आफ% कार्यक्रम कलैक्ट्रेट परिसर, रोशनाबाद में जिलाधिकारी द्वारा 4 अक्टूबर को 11.30 बजे किया जायेगा। इस दौरान एन.सी.सी. के कैडेट्स इशिका सिंह, अनन्या सिंह, मानसी चौहान एवं कसक, ग्राम प्रधान धनौरा शीला देवी, ब्लाक प्रतिनिधियों हवलदार किशन कुमार, हवलदार मेघराज, हवलदार अरविन्द कुमार, हवलदार सूरजपाल एवं हवलदार राजेश कुमार, बी.ई.जी. से सेवारत सैनिक नायब सूबे0 प्रमोद कुमार, हव0 गुरुप्रीत सिंह, हव जगमोहन, सूचना विभाग के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिकों व आश्रितों सहित कार्यालय के सहायक अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।

नेशनल चैंपियनशिप का हब बन रहा उत्तराखंड: रेखा आर्या

हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। शुक्रवार को प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में सीआईएससीई कबड्डी ब्वाएज चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। 3 से 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 35 टीमों हिस्सा ले रही है।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में पहचान बना रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हब बनता जा रहा है।

उत्तराखंड में हर सप्ताह नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित होने से भविष्य में यहां से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियन निकलेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुनहरा भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आउट ऑफ टर्न जॉब व सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जैसे प्रावधान किए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036



का ओलंपिक भारत में आयोजित करने को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में यह संभव है की कबड्डी जैसे परंपरागत खेल भी ओलंपिक का हिस्सा बन जाए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। हमने उत्तराखंड से कम से कम 40 एथलीट को 2036 की ओलंपिक में

शामिल कराने का लक्ष्य तय किया है। अवसर पर स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष स्वामी शरद पुरी महाराज, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, मेयर हरिद्वार किरण जैसल, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

संपादकीय

देश को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अब जनता को जागरूक होना होगा, अन्यथा देर हो जाएगी

जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सत्य-असत्य की पहचान करने लगते हैं, तभी समाज और देश सशक्त होता है। जागरूक जनता ही भ्रष्टाचार, अन्याय और गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर जागरूक बने, तो बड़े बदलाव स्वतः संभव हैं।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति और भलाई केवल सरकार या प्रशासन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब जनता जागरूक होती है, तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होते हैं। जनता की जागरूकता का अर्थ है-अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ, सत्य-असत्य की पहचान, और सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों पर सजग रहना। यदि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, चुनाव और नीतियों से जुड़े विषयों पर जागरूक रहेंगे, तो न केवल वे स्वयं सशक्त होंगे, बल्कि पूरे देश के विकास में योगदान देंगे।

आज के समय में जागरूक नागरिक ही गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही जनता लोकतंत्र की असली ताकत है। एक जागरूक समाज में न तो अंधविश्वास पनपता है, न ही अन्याय लंबे समय तक टिक पाता है। देश की भलाई के लिए जरूरी है कि जनता सही और गलत में अंतर करे, अपने अधिकारों का प्रयोग करे, कर्तव्यों का पालन करे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करे।

****उदाहरण**** हाल ही में एक छोटे से गाँव में, ग्रामीणों ने जागरूकता के बल पर अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, सामूहिक याचिका दायर की, और स्थानीय मीडिया के माध्यम से मुद्दे को उजागर किया। उनकी जागरूकता और एकजुटता के कारण अवैध खनन रुक गया, और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सका। यह उदाहरण दर्शाता है कि जागरूक जनता छोटे स्तर पर भी बड़े बदलाव ला सकती है।

देश की मालिक जनता को नेताओं, राजनेताओं, राजनीतिक दलों और पदाधिकारियों की झूठी जुमलेबाजी से बचना चाहिए। इतने वर्षों में वास्तविक हकीकत को देखकर और समझकर भी जनता जागरूक नहीं हो रही, यह अत्यंत दुःख है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, इसलिए जनता को चाहिए कि इतने वर्षों की मनमानी पर अंकुश लगाए। विशेष रूप से देश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करे। देश की मालिक जनता का आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक है। विचार करें कि अब तक कब और कहाँ धोखा नहीं खाया? किसने आपको धोखा दिया? इस पर अवश्य चिंतन करें।

अपनी भूल स्वीकार करते हुए जनता को चाहिए कि भूतकाल की गलतियों को दोहराए नहीं और सावधानी से कदम बढ़ाए। इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ जागरूक नागरिक बनें, समझदार बनें। समझदारी से ही गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। अपने साथ परिवार, परिवार के साथ राज्य, और राज्य के साथ हमारा प्यारा भारत देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर से वही गौरव प्राप्त कर सकता है, यदि जनता जागरूक होगी।

आज के समय में देश की सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ चौपट हो गई हैं। अधिकांश डुप्लिकेट सामानों का व्यापार देश में हो रहा है। सभी क्षेत्रों और विभागों को गंदा व्यापार और गंदा धंधा बना दिया गया है। यह समस्या केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। नेता, राजनेता, राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारी, यहाँ तक कि अधिकांश धर्मगुरु भी झूठे और डुप्लिकेट हो गए हैं। अधिकांश धर्मगुरु धन-दौलत के भूखे हैं; उन्हें सही-गलत से कोई सरोकार नहीं, केवल धन से मतलब है।

ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश धर्मगुरु भी डुप्लिकेट हो गए हैं, जो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। ये धर्मगुरु, नेता, राजनेता, राजनीतिक दल, उनके पदाधिकारी और बड़े-बड़े उद्योगपति व व्यापारी एक-दूसरे के दलाल बन चुके हैं। इनका एकमात्र मंत्र है-अपना खजाना भरना, चाहे तरीका गलत ही क्यों न हो। ये अपनी निजोरीयाँ देश के साथ-साथ विदेशों में भी भर रहे हैं। मौज-मस्ती और शौक पूरे करने में देश के धन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इन्हें पता है कि देश की जनता इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आरएसएस के 100 साल : उपलब्धियों और विवादों के नाम सनत जैन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह केवल किसी संगठन का शताब्दी पर्व नहीं, बल्कि उस विचारधारा की यात्रा है, जिसने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर से शुरू हुआ यह संगठन आज देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। इसके लाखों स्वयंसेवक शिक्षा, सेवा, संस्कार और संगठन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाजपा जैसी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को विचार और कार्यकर्ता देने में आरएसएस की भूमिका निर्विवाद है। जितनी मजबूती से यह संगठन आज खड़ा दिखता है, उतने ही विवाद भी इसके साथ जुड़े रहे हैं। आरएसएस पर शुरू से ही सांप्रदायिक होने और धार्मिक आधार पर समाज को बांटने के आरोप लगते रहे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। गांधी जी की हत्या के बाद देश में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल करने पर प्रतिबंध हट गया था। फिर भी यह सवाल हमेशा उठता रहा कि क्या आरएसएस का काम «सांस्कृतिक राष्ट्रवाद» तक सीमित है, या संघ राजनीति को परोक्ष रूप से नियंत्रित करता है? बीते दस दशकों में आरएसएस ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में अपनी

स्वीकार्यता बढ़ाई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय स्वयंसेवकों का काम भी सराहा गया है। लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच संघ को लेकर अविश्वास की खाई गहरी हुई है। संघ परिवार से जुड़े कुछ संगठनों की गतिविधियाँ और बयानों ने संघ की छवि को विवादास्पद एवं एक कट्टरवादी संगठन के रूप में बना दिया है। यही कारण है, कि सौ साल की यात्रा पूरी करने के बावजूद आरएसएस विवादों का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से भारत में पिछले एक दशक में धार्मिक उन्माद बढ़ाया गया और लगातार बढ़ाया जा रहा है, बार-बार हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर तरह-तरह के बयान संघ द्वारा पोषित अनुवांशिक संगठनों द्वारा दिए जाते हैं। एक तरह से मणिपुर में ईसाइयों का विरोध तथा संपूर्ण भारत में मुसलमान विरोधी संगठन के रूप में संघ की छवि बनी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, संघ और उसके अनुवांशिक संगठन आज एक भय के प्रतीक बनकर अपनी पहचान बना रहे हैं। जिसको लेकर समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा में उनके अच्छे और खराब सभी कामों का बड़-चढ़कर बखान किया जा रहा है। सवाल यही है, शताब्दी वर्ष में आरएसएस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के दिन अपने उद्बोधन में नेपाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक बार फिर नया विश्वास देने की कोशिश की है।

विश्व पशु कल्याण दिवस (4 अक्तूबर) पर विशेष)

एक-दूसरे के पूरक हैं मनुष्य और पशु

योगेश कुमार गोयल

पशुओं के कल्याण मानकों में सुधार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 4 अक्टूबर को ‘विश्व पशु कल्याण दिवस’ मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस पहली बार बर्लिन में 24 मार्च 1925 को पशु कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया गया था। पशुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए इटली के फ्लोरेंस में 1931 में आयोजित पारिस्थितिकीविदों के एक सम्मेलन में विश्व पशु दिवस की शुरुआत की गई और तब असीसी के सेंट फ्रांसिस के पर्व के कारण यह दिवस मनाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अक्तूबर को ही चुना गया। 2003 में पहली विश्व पशु दिवस वेबसाइट यूके स्थित पशु कल्याण चैरिटी ‘नेचर वॉच फाउंडेशन’ द्वारा लांच की गई थी। इस दिन पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्रति प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। पशुओं के अधिकारों के लिए यह एक ऐसी वैश्विक पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पशु कल्याण के लिए बेहतर मानक सुनिश्चित करना है।

पशु प्रेम के बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पशु मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि हमें बेहतर इंसान भी बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जानवर प्रकृति की पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य और पशु न केवल एक-दूसरे पर निर्भर हैं बल्कि एक-दूसरे के पूरक भी हैं। सही मायनों में दोनों का अस्तित्व ही खुशहाली का प्रतीक है और यदि जंगल से किसी एक जीव की प्रजाति भी लुप्त होती है तो उसका असर

सम्पूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है।

विश्व पशु दिवस विश्वभर में कल्याण मानकों के मिशन के साथ जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा सामाजिक आन्दोलन है, जो प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष ‘विश्व पशु कल्याण दिवस’ की थीम है ‘जानवरों को बचाओ, ग्रह को बचाओ!’। भारत में करीब 70 फीसद आबादी कृषि तथा कृषि संबंधी व्यवसायों पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही पशुपालन और कृषि व्यवसायों का आपस में गहरा संबंध रहा है। गरीबी से त्रस्त परिवारों के लिए तो पशुधन ग्रामीण मुद्राएं हैं, जो खासकर गरीब परिवारों के लिए बीमा विकल्प के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि यह उनके लिए ऐसी सम्पत्ति है, जिसे संकट के समय बेचा जा सकता है। यही कारण है पालतू पशुओं को ‘पशुधन’ कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी पशुधन की बड़ी भागीदारी रही है।

मानव और पशुओं के आपसी संबंध मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पशुओं का मानवीय समाज में विभिन्न रूपों में योगदान होता है। पशुओं के साथ रहने से हमें स्वभाविक संवेदनशीलता, प्यार, सहयोग और उन्नति का अनुभव होता है। बहुत से पशु-पक्षी तो ऐसे हैं, जो यदि धरती पर नहीं हों तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाएगा।

अनेक मामलों में देखा जाता है कि मानवीय स्वार्थ के लिए कई जानवरों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दरअसल इन पशुओं के विभिन्न अंग तथा उनके मल-मूत्र इत्यादि दवाइयां बनाने से लेकर खेतीबाड़ी तक में काम आते हैं और इनके कंकाल उर्वरक का काम करते हैं। हाथियों को हाथी दांत और गैंडे को उसके सींगों के लिए बेददी से मौत के घाट उतार दिया जाता है जबकि उनकी प्राकृतिक मौत होने पर ये चीजें वैसे ही मिल जानी होती हैं। हाथी और गैंडे कीचड़ में रहकर दूसरे जानवरों के पीने के लिए किनारे पर पानी का इंतजाम करते हैं और सूखा नहीं पड़ने देते। हाथी जमीन को उपजाऊ बना सकता है

राष्ट्रीय स्तरपर मोबाइल चोरों, ज़ेब से पैसे उड़ाने वाले हुनरमंद चोरों को हत्या व रेप की धाराओं में लाने की सख्त ज़रूरत

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर वर्तमान आधुनिक और डिजिटल युग में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जेबकटी, मोबाइल चोरी और डिजिटल वॉलेट से धन उड़ाने जैसी घटनाएं अब केवल स्थानीय समस्या नहीं रहیں, बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुकी हैं। आज के हुनरमंद चोर इतनी सफाई से काम करते हैं कि पीड़ितों को पता ही नहीं चलता कि उनकी जेब से पैसा या मोबाइल कब और कैसे गायब हो गया। यह अपराध केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सामाजिक असुरक्षा, मनोवैज्ञानिक दबाव और कानून व्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है।पीड़ित अक्सर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते- 25 पसेंट तक ही रिपोर्ट दर्ज होने का मैंने अंदाज लगाया हूं । रिपोर्टिंग न होने के कारण अपराधियों का डिटेक्शन और ट्रैकिंग मुश्किल होती है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र ऐसा मानता हूं कि आधुनिक शहरी भीड़, डिजिटल पेमेंट का प्रसार और त्योहारों पर बढ़ी भीड़-मास्ट्रेस का मिलन एक ऐसा परिदृश्य पैदा करता है जहाँ पारंपरिक जेबकटी अब केवल शौक्तीन अपराध नहीं बल्कि संगठित अपराधियों के लिए एक व्यवस्थित मुनाफ़े का साधन बन गया है। मोबाइल चुराने की कला सिर्फ़ «समर्थता» नहीं, बल्कि डिजिटलीकृत आर्थिक चोरी,जैसे मोबाइल वॉलेट रिक्त कर देना, ओटीपी चुराकर ट्रंज़ैक्शन करने में तब्दील हो चुकी है। दुनियाँ के कई बड़े शहरों में ऐसा देखा गया है कि भीड़-भाड़ वालेसार्वजनिक क्षेत्र और त्योंहारों के आयोजन अपराधियों के लक्षित क्षेत्र बन जाते हैं। भारत में भीइस और अपराध तेजी से बढ़ेहैं और अब यह अकेले व्यक्तिगत अपराध न रहकर रैकेट-आधारित संगठनों का हिस्सा बनते

जा रहे हैंहुनरमंद चोरों की विशेषता है उनकी चतुर्णई, टीमवर्क और भीड़-भाड़ का मूलभूत उपयोग। वे शोषण के ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनमें पीड़ितों को घटना का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मोबाइल की चोरी के साथ ही डिजिटल धन का दुरुपयोग सिम स्वैप, ओटीपी का व्यवधान, फोन चोरी कर फिर उससे बैंक एप्स के लॉगिन,जैसी तकनीकें जोड़ दी गई हैं। नतीजापीड़ित न केवल एक वस्तु खोते हैं बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा, निजी डाटा और भावनात्मक स्थिरता भी प्रभावित होती है। समाज पर इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षा का भाव, त्योहारों पर घबराहट और छोटे व्यवसायियों के लिए ग्राहकों का कम आना। साथियों बात अगर हम हुनरमंद चोरों की कार्यशैली और उनकी पहचान की करें तो,आधुनिक समय के जेबकतरे और मोबाइल चोर पारंपरिक चोरों से बिल्कुल अलग हैं। ये अपराधी न केवल शारीरिक रूप से चालाक होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद सजग रहते हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, धार्मिक मेले, त्योहारों के आयोजन, और मॉल्स में यह अपराधी अपनी «कला» का प्रदर्शन करते हैं।वे भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल और पर्स निकाल लेते हैं।कई बार दो-तीन लोगों का गैंग बनाकर काम करते हैंएक ध्यान भटकता है, दूसरा चोरी करता है और तीसरा माल लेकर तुरंत भाग जाता है।चोरी के तुरंत बाद मोबाइल का सिम निकालकर या उसे स्विच ऑफ करके ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं।इस स्थिति में पुलिस व जनता दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चेहरे पहचानना और अपराधियों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करना। अगर इन्हें पब्लिक डोमेन में उजागर किया जाए तो जनता सतर्क रहेगी और अपराधियों पर दबाव बनेगा।नवरात्र, दशहरा, दिवाली जैसे उत्सवों में

जबकि गैंडा कीचड़ में रहकर मिट्टी की अदला-बदली का काम करता है और प्रतिदिन करीब पचास किलो वनस्पति की खुराक होने से जंगल में कूड़ा-कर्कट नहीं होने देता। उसके शरीर पर फसल के लिए हानिकारक कीड़े जमा हो जाते हैं, जो पक्षियों का भोजन बनते हैं। इस प्रकार गैंडे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। वैसे तो सभी पशु-पक्षी मनुष्य के सहायक होते हैं लेकिन उनके व्यवहार को समझे बगैर यदि उनके रहने की जगहों को उजाड़ने के प्रयास किए जाते हैं तो वे हिंसक होकर विनाश कर सकते हैं।

तुर्की के विख्यात नाटककार, उपन्यासकार और विचारक मेहमत मूरत इल्डन का कहना था कि दुनिया में वन्यजीवों की रक्षा केवल दयालु दिलों के प्यार से ही की जा सकती है। वाइल्ड हार्ट वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक पॉल ऑक्सटन कहते थे कि जब तक आपके भीतर प्रकृति के बीच रह रहे जंगली जीवों के प्रति ढ़ेर सारा प्यार, दया और लगाव नहीं रहेगा, तब तक आप सच्चा सुख हासिल नहीं कर पाएंगे। मानव जाति को यह समझना होगा कि पशुओं का जीवन किसी भी तरह से हमारे जीवन से कम कीमती नहीं है। ‘जैव विविधता के जनक’ के नाम से विख्यात आधुनिक काल के डार्विन कहे जाने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीवविज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता ईओ विल्सन के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक प्रजाति अत्यधिक देखभाल एवं प्रतिभा के साथ बनाई गई रचना और एक उत्कृष्ट कृति है। वन्यजीव फोटोग्राफर, प्रकृतिवादी और ‘जॉय ऑफ बीयर्स’ सहित कुछ पुस्तकों की लेखिका सिल्विया डोलसन कहती हैं कि हमारी ही तरह जानवर भी प्यार, खुशी, डर और दर्द महसूस करते हैं लेकिन वे बोले गए शब्द को समझ नहीं पाते, अतः यह हमारा दायित्व है कि हम उनकी ओर से बोलें और सुनिश्चित करें कि उनकी भलाई और जीवन का सम्मान एवं सुरक्षा हो। इसके लिए प्रकृति और पशुओं के साथ अपने संबंधों में मनुष्य को सन्ध बनाना आवश्यक है।

लोगों का मन त्योंहार, खरीदारी और उत्साह में रम जाता है।अपराधी इन्हीं मौकों पर सक्रिय होते हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अक्सर सामान्य से ढीली रहती है और भीड़ का भौतिक वातावरण अपराधियों को कामयाबी देता है। धार्मिक स्थलों, मॉल, मेट्रो स्टेशन, लोकल ट्रेन और मेले – ये सब उच्च जोखिम वाले स्थल बन जाते हैं। इसलिए त्योहारों के दौरान न केवल अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है बल्कि विशिष्ट तकनीकी और सामुदायिक उपायों की भी आवश्यकता है।त्योहारों में भीड़ का फायदा उठाकर जेबकटी और मोबाइल चोरी बढ़ जाती है।लोग उत्सव के माहौल में लापरवाह हो जाते हैं और सतर्कता कम हो जाती है।कई बार चोर धार्मिक स्थलों, पंडालों और रथयात्राओं की भी निशाना बनाते हैं।इसलिए पुलिस को विशेष रूप से त्योहारों के समय अपराध नियंत्रण शाखा और मोबाइल स्क़ाड जैसी विशेष इकाइयां गठित करनी चाहिए।ट्रेन सर्विलांस, सीसीटीवी और ईटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करके ही इस चुनौती से सख़्ती निपटा जा सकता है।

साथियों बात अगर हम मोबाइल चोरों और जेबकतरों के लिए कड़ी सज़ा-हत्या और रेप जैसे अपराधों की श्रेणी में लाने की मांग को समझने की करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोरी के मामलों के लिए जो धाराएं लागू होती हैं, उनमें अधिकतम सज़ा 3 से 7 साल तक की है। लेकिन मोबाइल और डिजिटल धन की चोरी आज के युग में सिर्फ़ मामूली चोरी नहीं रही। यह अपराध (1)सैकड़ों लोगों को कंगाल बना देता है (2)पीड़ितों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है (3)डिजिटल फाइनेंस की विश्वसनीयता पर चोट करता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे अपराधों को केवल संपत्ति से जुड़ा अपराध न मानकर, इसे गंभीर सामाजिक अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों में जन सहभागिता पर दिया जोर

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 09 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए तथा इस अवसर पर जन सामान्य की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न होकर जन-जन का उत्सव बने। इसके लिए विशेष तैयारी और योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना होगा।

नन्दा राज जात यात्रा मार्गों का रखरखाव

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को नन्दा राज जात यात्रा मार्गों के रखरखाव और यात्रा के रात्रि पड़ाव स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना शीघ्र तैयार



करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उत्तराखण्ड की संस्कृति, परंपरा और आस्था जुड़ी है, इसलिए इसमें यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

आपदा प्रबंधन कार्यों की सराहना

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश में हाल ही

में आई आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सभी संबंधित संस्थानों व अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में तेजी और समन्वय से ही जनहानि को कम किया जा सकता है।

शहरों में यातायात और स्वच्छता पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शहरों में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत करने और खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पलैंगशिप योजनाओं का पूरा ब्यौरा

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश में पूर्ण होने वाली पलैंगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा विवरण तैयार करने को भी कहा, ताकि विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जा सके।

सड़क निर्माण व गड्ढा मुक्त अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश में निर्माण और नव-निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण

और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। 31 अक्टूबर तक पैच वर्क कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, सचिव विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विकास योजनाओं के लिए दी 986 करोड़ की स्वीकृति

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 986 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें भवन निर्माण, सड़क, पुल, सिंचाई, विद्युत, पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के कार्यों को पूरा कराया जायेगा।

भवन एवं बुनियादी ढांचा विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत जनपद के बाराकोट तहसील के अनावासीय भवन निर्माण के लिए 3.03 करोड़, हरिद्वार में ऑफिसर्स कॉलोनी में श्रेणी-05 के दो शासकीय आवासों के लिए 1.86 करोड़, पौड़ी

गढ़वाल तहसील कार्यालय में मीटिंग हॉल व अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 2.08 करोड़ और लोहाघाट बस स्टेशन पर कार्यालय भवन, कार्यशाला व स्टोर निर्माण हेतु 7.16 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

पंचायतों और शहरी निकायों के लिए वित्तीय सहायता

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों को 83.25 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 78 करोड़ और ग्राम पंचायतों को 200 करोड़ की राशि अवमुक्त की जाएगी।

इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों को 333 करोड़ और तीन गैर-निर्वाचित निकायों

को 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

सड़क एवं पुल निर्माण

मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अनास्वाला-मालसी मोटर मार्ग पर किमी 4 से 7 तक पुनर्निर्माण कार्य हेतु 3.19 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई।

बागेश्वर में सरयू नदी पर 113 वर्ष पुराने पैदल झूला पुल के जीर्णोद्धार और देहरादून के काठ बंगला हाउसिंग सोसाइटी में विद्युत कनेक्शन व पेयजल लाइन बिछाने हेतु 4.16 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में खनिया नम्बर-4 के जयनगर रोड से शिव मंदिर मार्ग तक हॉटमिक्स रोड और उससे जुड़े

मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक कोटद्वार क्षेत्र में खोह नदी के बाएं तट पर ग्राम ग्रास्टनगंज की बाढ़ सुरक्षा हेतु 5.81 करोड़ स्वीकृत किए गए।

विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में नवाबगढ़ पुल संख्या-1 से खादर तक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 3.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा एवं विश्वविद्यालय विकास

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय चम्पावत परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय, चहारदीवारी और मिनी स्टेडियम निर्माण के

लिए 2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं

नाबाई वित्त पोषण से सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के लिए 52.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड ट्रांसमिशन स्ट्रेथनिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन इम्पूवमेंट प्रोग्राम (एडीबी योजना) के तहत विभिन्न कार्यों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। विशेष घोषणाएं: बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में ग्राम सभा सीमा स्थित एनजेडी बबू मंदिर स्थल के विकास हेतु 97.20 लाख और पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रैछड़ा से इंटर कॉलेज मट्टमानले तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 23.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को फटकारा, छात्रा को सात दिन में मिलेगी डिग्री

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन 1905 से जुड़ी तमाम शिकायतों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। पीड़ितों को फोन करके उनकी शिकायतों के निस्तारण की जानकारी जुटा रहे थे। टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी ने डिग्री न मिलने की शिकायत

सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज कराई थी, लेकिन निस्तारण न होने पर सचिवालय में समीक्षा बैठक में मामला सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने आ गया। मुख्यमंत्री ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और तुरंत सचिव आईटी तथा सचिव उच्च शिक्षा को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने और जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि छात्रा को सात दिन के भीतर डिग्री उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए जाएं।

शिकायतकर्ता से सीधे बातचीत, अधिकारियों को चेतावनी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बात भी की और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जो शिकायतें समय सीमा में निस्तारित नहीं होंगी, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी।

लंबित मामलों का अभियान चलाकर निस्तारण

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों



को निर्देश दिया कि वे हर सप्ताह हेल्पलाइन की समीक्षा करें, सचिवगण माह में दो बार और मुख्य सचिव हर माह समीक्षा करें। तीन माह से अधिक लंबित मामलों का अभियान चलाकर निस्तारण किया जाए।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता

उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों और सुरक्षा दीवारों की मरम्मत को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान केवल कागजों में नहीं, बल्कि ज़मीनी

स्तर पर होना चाहिए।

पेयजल, गृह और ऊर्जा विभाग पर सबसे ज्यादा शिकायतें

निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर सर्वाधिक शिकायतें पेयजल, गृह विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़ी प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वचुंअल माध्यम से जुड़े रहे।

एक नजर

देश में सामाजिक सुरक्षा हो रहा मज़बूत : मांडविया

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में व्यापक नीति, प्रक्रिया और डिजिटल सुधारों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत बनाया जा रहा है। भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डॉ. मांडविया ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आईएसएसए विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत समावेशी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत होने और 940 मिलियन से अधिक नागरिकों तक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता दिए जाने पर भारत को %सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि% के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि के बाद, भारत ने आईएसएसए महासभा में 30 सीटों के साथ सर्वोच्च वोट शेयर हासिल किया है। डॉ. मांडविया ने कहा, "यह पुरस्कार श्री मोदी के दृष्टिकोण और अंत्योदय के हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रमाण है, जो पवित्र में अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाता है, जिसने समावेशी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में हमारी यात्रा को आकार दिया है।"

केंद्रीय मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए भारत में व्यापक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, "ई-श्रम पोर्टल एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस है जो एक बहुभाषी, निर्बाध इंटरफ़ेस के माध्यम से 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने वाले "वन-स्टॉप सोल्यूशन" के रूप में कार्य करता है।"

उन्होंने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का भी उल्लेख किया, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साझा मंच पर लाने के लिए मजबूत डिजिटल उपकरणों से लैस है। उन्होंने कहा, "आज, एनसीएस के पास कुशल कार्यबल का एक प्रमाणित डेटाबेस है, जो दुनिया भर के नियोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध है और ई-श्रम के साथ एकीकृत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल हमारे कुशल युवाओं की सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ वैश्विक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।"

डॉ. मनसुख मांडविया ने तकनीकी और श्रम बाजार में बदलावों के साथ सामाजिक सुरक्षा की उभरती भूमिका उल्लेख करते हुए कहा कि "हम व्यापक नीति, प्रक्रिया और डिजिटल सुधारों के माध्यम से अपनी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। भारत वित्तीय पहुंच, कोशल विकास, स्व-रोज़गार और डिजिटल नवाचार को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से आय के नए अवसरों और सामाजिक सुरक्षा के लिए तकनीक का लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा, भारत भविष्य को आकार देने और दुनिया के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।





डॉ.आरएस.टोलिया सूचना का अधिकार वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025 में दून विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज चैंपियन

पथ प्रवाह संवाददाता

उत्तराखंड में सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दून विश्वविद्यालय के सभागार हॉल में शुक्रवार को डॉ. आरएस. टोलिया राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड सूचना आयोग और दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था - आरटीआई से सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलती है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को सशक्त बनाने का सबसे मजबूत साधन है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होता है, सरकारी व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनती है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। कुलपति प्रो. डॉ. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को आरटीआई की महत्ता और उसकी उपयोगिता से जोड़ना है। उन्होंने प्रतिभागियों की तार्किक क्षमता, प्रस्तुति कौशल और बहस की गुणवत्ता की सराहना की। निर्णायक मंडल में अजय जुगरान, डॉ.



कंचन नेगी और रीना तिवारी शामिल रहे, जिन्होंने निष्पक्ष निर्णय द्वारा विजेताओं का चयन किया।

विजेताओं की सूची

प्रथम पुरस्कार: अभिनव त्रिपाठी, डीएसबी नैनीताल (10,000)
द्वितीय पुरस्कार: रेखा पंवार, राजकीय पीजी कॉलेज नई टिहरी (7,500)
तृतीय पुरस्कार: स्वाति, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज (5,000)
विशेष पुरस्कार: शिव्या, दूर विश्वविद्यालय (5,000)

प्रतियोगिता में कुल 29 विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। प्रतिभागियों ने अपने तर्क और प्रस्तुति कौशल से दर्शकों और निर्णायक मंडल को प्रभावित किया।

प्रतिभागियों में प्रमुख विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

राजकीय पीजी कॉलेज पिथौरागढ़, खटीमा, कोटद्वार, कोटाबाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, ऋषिकेश, पाटी, थर्यूड़, पौड़ी, रामनगर,



जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, एसजीआरआर कॉलेज, देहरादून आदि शामिल थे। मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी और कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल ने प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए व्यवस्थापकों और विश्वविद्यालयों को धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता में डॉ. चेतना पोखरियाल (डीन), डॉ. अदिति (एसोसिएट प्रोफेसर) का विशेष आभार व्यक्त किया गया। उत्तराखंड सूचना आयोग के

अनुसार, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राज्य के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को आरटीआई के महत्व से अवगत कराना इस कार्यक्रम की प्राथमिकता रही। आयोजन की सफलता: मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, दिलीप सिंह कुंवर, कुशलानंद, देवेन्द्र कुमार आर्य, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, सचिव रजा अब्बास, उप सचिव युक्ता मिश्र उपस्थित रही।

आपदाग्रस्त धराली पहुँचे सचिव सिचाई युगल किशोर पंत, प्रभावितों से की वार्ता - पुनर्वास, रोजगार और सड़क बहाली का दिलाया भरोसा

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। सीमांत क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल-धराली एवं आसपास के गाँवों में आई आपदा की स्थिति का जायजा लेने शुक्रवार को सचिव सिचाई युगल किशोर पंत पहुँचे। उन्होंने मौके पर जाकर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गहराई से सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने पुनर्वास, रोजगार और आजीविका से जुड़ी परेशानियों को विस्तार से रखा। सचिव ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा से हुई क्षति का आकलन शीघ्र कर लिया जाएगा और पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने हर्षिल में बनी अस्थायी झील की स्थिति भी देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों और यात्रियों की सुरक्षा



सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार आपदा प्रभावित

परिवारों को राहत और पुनर्वास देने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगी और प्रभावित लोगों को स्थायी रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। सचिव पंत ने धराली स्थित आर्मी बेस कैंप का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर आपदा के दौरान हुई क्षति की जानकारी ली। जवानों ने उन्हें बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण सैन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और रसद व शस्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में कठिनाई आ रही है। इस पर सचिव ने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर तत्काल वार्ता की जाएगी और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

आपदा प्रभावित धराली व हर्षिल क्षेत्र के लोगों से हुई इस संवाद के बाद ग्रामीणों ने राहत की उम्मीद जताई और कहा कि यदि सरकार व प्रशासन ने वादे के अनुरूप त्वरित कार्रवाई की तो उनका जीवन सामान्य होने लगेगा।

शहीद सम्मान यात्रा को गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और एडीएम मुक्ता मिश्र ने दिखाई हरी झंडी, टिहरी होते हुए पहुंचेगी लैंसडाउन

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय से शुक्रवार को शहीद सम्मान यात्रा पूरे विधि-विधान और सम्मान के साथ रवाना की गई। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान एवं अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे के लिए प्रेषित किया।

यह यात्रा आज टिहरी पहुंचेगी जबकि कल लैंसडाउन पहुंचेगी, जहां वीर सपूतों की अमर गाथा को सलामी दी जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार को वीर शहीद रायचन्द असवाल (ग्राम बगासू) एवं राइफल मैन शैलेन्द्र सिंह कठैत (ग्राम कुमराड़ा) के पैतृक घर-आंगन से मिट्टी कलश में भरकर जिला मुख्यालय लाया गया था। उसी मिट्टी को आज श्रद्धा व सम्मान के साथ आगे रवाना किया गया। इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान एवं अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने कहा कि देश की आन-बान-शान के लिए अपने



प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीद परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शहीदों को नमन किया और

श्रद्धांजलि अर्पित की। यह शहीद सम्मान यात्रा न केवल वीर सपूतों की शहादत को नमन है बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला संदेश भी है।

जनसुनवाई में उठा छात्रों और किसानों का मुद्दा, डीएम ने दिए तत्काल कार्यवाही के आदेश

डीएम आर्य बोले- पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, जैविक खाद उत्पादन को मिले बढ़ावा



संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिला कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न वर्गों के लोग अपनी समस्याएं लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के समक्ष पहुंचे। डीएम आर्य ने गंभीरता से सभी पक्षों को सुना और मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान कराया। इस दौरान छात्रों से लेकर किसानों तक की समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। सबसे पहले जिला मुख्यालय के अम्बेडकर भवन स्थित पुस्तकालय से जुड़े छात्र-छात्राओं ने जिलाधिकारी को बताया कि 6 अगस्त को वरुणावत पर्वत से भारी गड़ और मलबा परिसर में भर गया था। इसके कारण पुस्तकालय का वातावरण प्रभावित हो गया है और अध्ययन करने में कठिनाई हो रही है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर मानते हुए स्पष्ट कहा कि परीक्षार्थियों और छात्रों की पढ़ाई किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डीडीएमओ को तत्काल पीडब्ल्यूडी की मदद से सफाई कार्य शुरू

कराने के आदेश दिए। वहीं, नौगांव विकासखंड के तियाँ गांव के निवासी जयप्रकाश थपलियाल ने केंचुआ खाद प्लांट के विस्तारीकरण की मांग रखी। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग व सीएचओ को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर शीघ्र उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि जैविक खाद उत्पादन किसानों के लिए लाभकारी है और जिले में इसकी संभावनाएं बढ़ाई जानी चाहिए। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से साफ कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन की प्राथमिकता जनहित है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह जनसुनवाई जहां छात्रों की पढ़ाई से जुड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकेत देती है, वहीं किसानों को जैविक खाद उत्पादन के माध्यम से सशक्त बनाने की पहल भी दर्शाती है।



एक नजर

दशहरे पर बेरीनाग पुलिस ने 14 जुआरी पकड़े



पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। एसपी पिथौरागढ़ के निर्देश पर सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी, सीओ केएस रावत के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा जुआरियों और सटोरियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी थानाध्यक्ष बेरीनाग हरीश सिंह कोरंगा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत 14 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। इस दौरान इनके पास से 49750 रुपये बरामद हुए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेरीनाग में धारा-13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बलुवाकोट पुलिस ने छात्र-छात्राओं को किया जागरूक



पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। थानाध्यक्ष बलुवाकोट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आश्रम पद्मिनी स्कूल बलुवाकोट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को साइबर क्राइम समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए उसके बचाव के उपाय भी बताए। सभी छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने के लिए कहा गया। इस दौरान प्रचलित विभिन्न पोर्टल जैसे सीटीजन पोर्टल, उत्तराखण्ड पुलिस एप, साइबर क्राइम पोर्टल आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नशे के दुष्परिणाम अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक एवं विधिक विषयों पर भी जागरूक किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं में कानून के प्रति सम्मान, आत्म-सुरक्षा की समझ तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से की गई सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा



जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम हेल्प लाइन 1905 में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर फीडबैक अवश्य प्राप्त किया जाए, ताकि समाधान की गुणवत्ता का आकलन हो सके। जिन विभागों में लंबित शिकायतों की संख्या अधिक है, वे प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करें। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का डेली मॉनिटरिंग किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। जिन शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, उनकी जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि समाधान संतोषजनक है या नहीं। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, अधीक्षण अभियंता लोनिवि, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी सदर मनजीत सिंह, सीएमओ डॉ. एस.एस. नबियाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

दिवंगत पत्रकार राजीव प्रताप प्रकरण SIT रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट, पर अनसुलझे रहे कई सवाल

संवाददाता - ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के डिजिटल पत्रकार राजीव प्रताप (36 वर्ष), पुत्र मुरारी लाल, निवासी अजबपुर कला, देहरादून की गुमशुदगी और फिर शव बरामदगी ने पूरे उत्तराखण्ड की पत्रकारिता जगत को झकझोर दिया है। इस बहुचर्चित मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अब अपनी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 18 सितम्बर की देर रात राजीव प्रताप अपने साथियों संग बाजार और होटल में खाना-पीना करने के बाद करीब 11:38 बजे गंगोरी पुल के CCTV कैमरे में अंतिम बार नजर आए। इसके बाद उनकी गाड़ी किसी अन्य कैमरे में नहीं दिखी। 19 सितम्बर को SDRF/NDRF की टीम को गंगोरी क्षेत्र में नदी के भीतर एक वाहन दिखाई दिया। जांच पर यह वही कार निकली जिसे राजीव प्रताप चला रहे थे। गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक थे, शीशे ऊपर थे और इग्निशन ऑन था। कार से सिर्फ एक नीली चप्पल बरामद हुई। लगातार 10 दिन की खोजबीन के बाद 28 सितम्बर की सुबह 11:05 बजे SDRF/NDRF ने जोशीयाड़ा बैराज से शव निकाला। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि मृत्यु का कारण छाती व पेट की आंतरिक चोटों से हुआ हैमरेज और शॉक था। ये चोटें वाहन के नदी में गिरने और स्टेयरिंग से टकराने पर आईं। महत्वपूर्ण बात यह रही कि शव पर किसी बाहरी हमले या मारपीट के निशान नहीं पाए गए। SIT ने प्राथमिक तौर पर इसे हादसा माना है, लेकिन मृतक पत्रकार के परिजन कई अनसुलझे सवाल उठा रहे हैं। गाड़ी सड़क से नीचे कैसे गिरी, शव 10 दिन तक नदी में रहने के बाद भी सामान्य अवस्था में कैसे मिला, और दिवंगत पत्रकार की पत्नी का कहना है कि राजीव प्रताप को उन्हें उनके काम को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं—ये सभी सवाल



अब भी जांच को नई दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए SIT से निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। 1 अक्टूबर को सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी राजीव प्रताप के दीपनगर स्थित आवास पहुँचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं पत्रकार संगठनों ने राजीव प्रताप के निधन को पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति बताते हुए इस मामले में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है।

इस बीच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) जनक सिंह पंवार, जो SIT की अगुवाई कर रहे हैं, ने

प्रेस वार्ता में कहा कि परिजनों द्वारा जताई गई आशंकाओं और बताए गए सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच की जा रही है। CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान का मिलान किया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर अमल किया जाएगा और अगली विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। फिलहाल SIT की रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हुआ है कि राजीव प्रताप की मौत नदी में वाहन गिरने से हुई, लेकिन गाड़ी के गिरने की परिस्थितियां, शव की स्थिति और धमकियों के एंगल जैसे कई अहम प्रश्न अब भी जस के तस हैं। यही कारण है कि सभी की निगाहें SIT की आगे की जांच और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।

खोया पर्स बरामद कर 60 हजार रुपये वापस लौटाए

पथ प्रवाह संवाददाता।

पिथौरागढ़। जाजरदेवल पुलिस ने एक व्यक्ति के खोए पर्स को ढूंढकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक बिखर दी। पर्स में 60 हजार रुपये भी रखे थे, जिन्हें सही सलामत मालिक को वापस लौटाए गए।

पुलिस के मुताबिक 2 अक्टूबर को रवि धामी, जो कि होन्डा शोरूम के मैनेजर हैं, अपनी पत्नी के साथ शोरूम से घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी का पर्स जाजरदेवल क्षेत्र में कहीं गिर गया, जिसमें 60 हजार रुपये थे। पर्स के खो जाने की सूचना रवि धामी द्वारा थाना जाजरदेवल में 03.10.2025 को दी गई थी। सूचना मिलते ही, थानाध्यक्ष मनोज पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्परता से खोजबीन शुरू की। टीम में हे0का0 मनोज



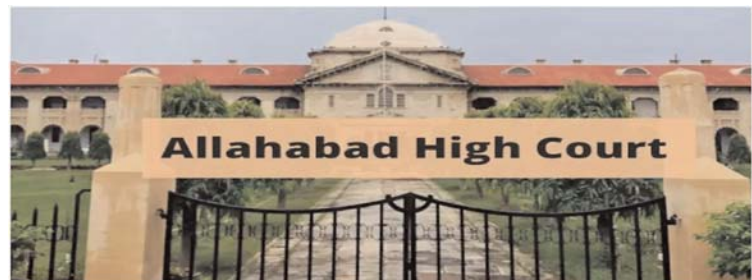
कुमार, का0 ध्रुव सिंह और म0का0 अंकिता शामिल थे। लगभग एक घंटे के भीतर ही पर्स और उसमें रखे हुए 60 हजार रुपये जाजरदेवल क्षेत्र से बरामद कर लिए गए और

फिर इन्हें सुरक्षित रूप से रवि धामी के सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्यवाही से पुलिस ने तत्परता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।

एफएसएल की रिपोर्ट केवल पुष्टिकारी साक्ष्य - हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेस (एनडीपीएस) एक्ट से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट केवल पुष्टिकारी साक्ष्य होती है और इसे आरोप पत्र के साथ न जोड़ने मात्र से आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। खासकर जब मामला व्यावसायिक मात्रा का हो। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज थाने में दर्ज एनडीपीएस केस में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुनाया।

आरोपी रणधीर को 2023 में हरियाणा नंबर की एक डीसीएम ट्रक से 1511600 किलोग्राम गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक श्रेणी में आती है। आरोपी के खिलाफ धारा 8/20 के तहत एफआईआर



दर्ज की गई थी। रणधीर की पहली जमानत याचिका 12 अगस्त 2024 को खारिज हो चुकी थी। वहीं दूसरी याचिका में उसने तर्क दिया कि वह दिहाड़ी मजदूर है और आरोप पत्र में एफएसएल रिपोर्ट न होने के कारण उसे जमानत मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने साफ किया कि एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति आरोप पत्र को अधूरा नहीं बनाती, जब जांच अधिकारी के पास पहले से पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों। इस रिपोर्ट

केवल पहले से एकत्रित साक्ष्यों की पुष्टि करती है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है। सरकारी वकील ने दलील दी कि गांजा की बरामदगी जानबूझकर की गई थी और एफएसएल रिपोर्ट बाद में केस डायरी का हिस्सा बना दी गई थी, जो सीआरपीसी की धारा 293 के तहत स्वीकार्य है।

प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 'पंचम धाम-सैन्यधाम' ले रहा आकार: सांसद त्रिवेन्द्र रावत

शहीदों के आँगन की मिट्टी, मातृभूमि-भक्ति की अमर गाथा का जीवंत प्रतीक-त्रिवेन्द्र

पथ प्रवाह, संवाददाता, देहरादून

हरिद्वार लोकसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज अपने संसदीय क्षेत्र की विंडलास रिवर वैली हाउसिंग सोसाइटी, देहरादून में शौर्य चक्र से सम्मानित वीर बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह जी के पावन आँगन से पवित्र रज का संकलन किया। सांसद श्री रावत ने कहा कि यह रज केवल मिट्टी नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और मातृभूमि-भक्ति की अमर गाथा का जीवंत प्रतीक है। इसमें उस अदम्य साहस की गूँज है, जिसने भारत माँ की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने स्मरण कराया कि जब उन्हें उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मुख्यसेवक के रूप में मिला, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीरभूमि उत्तराखंड में शहीद सैनिकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प के परिणामस्वरूप अब ःपंचम धाम-सैन्यधामः



आकार ले रहा है। सांसद त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह धाम केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण होगा। यह उन अमर वीरों का पवित्र तीर्थ बनेगा,

जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए। आने वाली पीढ़ियाँ इस स्थल पर आकर यह प्रेरणा पाएंगी कि राष्ट्र सर्वोपरि है और



हमारे वीर सैनिक भारत माँ का सर्वोच्च गौरव हैं। इस अवसर पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, जिला समाज कल्याण अधिकारी कर्नल ओ.पी. फर्शावाण, मेजर

महावीर सिंह रावत, महासचिव देवेन्द्र डोभाल, सुभाष भट्ट, भोपाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पौराणिक तीर्थों का भ्रमण करने के लिए हरिद्वार से रवाना हुई जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा शुक्रवार को हरिद्वार से उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थों के भ्रमण के लिए रवाना हो गयी। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमहंत अवधेशानंद गिरि महाराज ने माया देवी मंदिर तथा श्री आनंद भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात छड़ी यात्रा को रवाना किया।

जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि महाराज के मार्गदर्शन निकाली जा रही छड़ी यात्रा प्रमुख छड़ी महंत हिमालय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर वीरेंद्र आनंद गिरि महाराज के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करेगी। छड़ी यात्रा को रवाना करने के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो व लोगों को रोजगार मिले, उपेक्षित तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार हो और उनका प्रचार-प्रसार कर उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से ही हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

श्रीमहंत हरि गिरि महाराज ने कहा कि उत्तराखंड की सुख-समृद्धि, विकास, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के साथ दुर्गम क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थान, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए जाने के उद्देश्य से यह यात्रा की जा रही है। सुविधाएं मिलने से जहां पलायन रुकेगा, वहीं सीमांतवर्ती क्षेत्र की सीमाओं की



सुरक्षा होगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए पलायन पर अंकुश लगाना जरूरी है। पवित्र छड़ी यात्रा लोगों के साथ सरकार को भी जागरूक करेगी ताकि उत्तराखंड का विकास हो और पलायन रुके। महंत विरेन्द्रानंद गिरि महाराज ने कहा कि पवित्र छड़ी के माध्यम से उत्तराखंड के उपेक्षित पौराणिक तीर्थों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उपेक्षित पौराणिक तीर्थों का जीर्णोद्धार होने से विकास से वंचित क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। माया देवी मंदिर से ऋषिकेश के लिए रवाना होने के पश्चात छड़ी यात्रा का गोकर्ण आश्रम, भल्ला गिरि आश्रम व स्वतंत्र पुरी आश्रम में स्वागत हुआ। शुक्रवार को पवित्र छड़ी यात्रा ऋषिकेश में तारादेवी मंदिर, त्रिवेणी

घाट, दुर्गा मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, मायाकुंड, भरत मंदिर पहुंची। सभी जगह पवित्र छड़ी यात्रा का हजारों संतों व भक्तों ने स्वागत किया। गंगा की पूजा-अर्चना के पश्चात यात्रा ने रात्रि विश्राम ऋषिकेश में किया। छड़ी यात्रा में लगभग सौ नागा संन्यासियों का जत्था जा रहा है।

इस अवसर पर जूना अखाड़े के महामंत्री श्रीमहंत महेश पुरी महाराज, श्रीमहंत शैलेंद्र गिरि महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमहंत केदारपुरी महाराज, मंत्री व दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री श्रीमहंत कंचन गिरि महाराज, श्रीमहंत महाकाल गिरि महाराज, जूना अखाड़ा माई बाड़ा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत अन्नपूर्णा पुरी महाराज, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरि महाराज, श्रीमहंत आदित्य गिरि महाराज, श्रीमहंत पशुपति गिरि महाराज, कमल खड़का आदि मौजूद रहे।

भूगोल में रहना है या नहीं रहना.....आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उषेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि इस बार भारत पहले की तरह संयम नहीं बरतेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कि पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं।

राजस्थान के अन्पगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा, कि इस बार हम उस तरह से संयम नहीं बरतेगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में किया गया था। इस बार भारत ऐसा कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में रहना है, तो उसे राज्य-प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक चार-दिवसीय टेस्ट मैच की तरह बताया और कहा कि युद्ध कभी भी योजना के मुताबिक नहीं चलता। उन्होंने सेना को हर



स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। इससे एक दिन पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। गुजरात के भुज में शस्त्र पूजा के अवसर पर उन्होंने सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की हरकतों का उल्लेख करते हुए कहा था, कि पड़ोसी देश को सुधर जाना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले

ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ निलंबित है, बंद नहीं हुआ है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी, इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। भारत ने हाल ही में यह नीति भी तय की है, कि आतंकवादियों के साथ-साथ उनके समर्थकों से भी उसी कठोरता के साथ निपटा जाएगा।

एक नजर

‘ई-स्पोर्ट्स’ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता मिलेगी

नई दिल्ली। इस माह ड्राफ्ट रूलस जारी होने के साथ ‘ई-स्पोर्ट्स’ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता मिलने जा रही है। यह मसौदा भारतीय ई-गेमिंग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। ई-स्पोर्ट्स को ‘द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूलस 2025’ के अंतर्गत लाकर अब विशेष रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत विनियमित किया जाएगा। यह व्यवस्था ई-स्पोर्ट्स को जुए के साथ होने वाले भ्रम और नियामक अव्यवस्था से बाहर निकालकर एक स्पष्ट पहचान देगी। इसके साथ ही, एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ईस्पोर्ट्स टाइटल्स को रजिस्टर करेगी। यह अथॉरिटी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी और शिकायतों का निपटारा करेगी। देखा जाए तो, अब ई-स्पोर्ट्स को वही प्रशासनिक ढांचा मिला है, जो क्रिकेट या हॉकी में देखने को मिलता है। अब ई-स्पोर्ट्स को कौशल-आधारित, प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में माना जाएगा, जो किसी फैंटेसी या किस्मत पर आधारित गेम से अलग है। यानी जुए से जुड़े टाइटल्स बाहर रहेंगे। वहीं, मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स को सरकारी संरक्षण, वित्तीय पोषण अवसर और आधिकारिक खेल आयोजनों के रूप में आयोजित किए जाने का अधिकार मिलेगा।

लोन फ्राँड केस में अनिल अंबानी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया। स्टेट बैंक ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में चिह्नित किया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और आरोप लगाया था कि उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन की हेराफेरी की गई है। अंबानी ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद दिए गए। बैंक ने इस साल केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई।

एसबीआई ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी।

हरिद्वार से निकलने वाली गंगनहर बंद

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तरप्रदेश के कानपुर तक बहने वाली गंगनहर को मेटेनैस के लिए 19 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है, जिससे उत्तरप्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ किसानों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तरप्रदेश के 5 जिलों के किसान सिंचाई के लिए इस नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। गंगनहर उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली एक विशाल सिंचाई नहर प्रणाली है। इसे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1842 से 1854 के बीच बनाया गया था। शुरुआत में इसका उद्देश्य दोआब क्षेत्र (गंगा और यमुना नदियों के बीच का इलाका) की खेती को पानी देना था।

चैतन्यानंद की तीन महिला सहयोगी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की तीन करीबी महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पृष्ठछाछ में महिलाओं ने माना कि उन्होंने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया। गिरफ्तार महिलाओं में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (एजीक्यूटिव डायरेक्टर) और काजल (सीनियर फैकल्टी) शामिल हैं। आरोप है कि इन्होंने अपराध में सहयोग, शिकायतकर्ताओं को धमकाया और सबूत नष्ट किए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गैस्ट हाउस में चैतन्यानंद महिला छात्रों के साथ रुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें वह एक वॉट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है।